(a) details of projects proposed to be implemented in terms of 10 per cent Budgetary allocation for North-East Region under Prime Minister's special package;

(b) budgetary allocations made against such projects during 1997-98 and 1998-99, State-wise;

(c) whether proposal for (i) declaring Majuli as world heritage site and (ii) Eco-stabilisation and conservation of Majuli Island was submitted by the Government of Assam; and

(d) if so, the status of their implementation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS, MINIS- TER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): (a) and (b) A Non- lapsable Central Pool of Resources has been constituted during 1998-99 from out of unspent amount(s) from 10% of the Budget(s) of the concerned Central Ministeries/Departments earmarked for the North-East and Sikkim to assist development projects, including from Prime Minister's package, in these States. Releases amounting to Rs. 93.10 crores have recently been made from the Central Pool for projects in the North-East.

(c) and (d) A proposal for declaring the Majuli River Island in Assam as a World Heritage site has been received and is being examined. A project titled "Eco-stabilisation and conservation of Majuli Island" was also received from the Gover- nment of Assam. It was found that the project proposal was not in conformity with the guidelines prescribed for the major afforestation schemes. The State Government have, therefore, been advised to recast the project proposal as per the guidelines.

विभिन्न राज्यों में विकास योजनाएं

2609. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को अनुमोदित करते समय गुजरात और मध्य प्रदेश से संबंधित किन-किन योजनाओं को विशेष महत्व दिया गया था;

(ख) इन राज्यों में संसाधनों को जुटाने और इसके ढांचागत आवंटन के बारे में कोई परिवर्तन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन राज्यों के विकास में तर्कसंगतता लाने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा, गुजरात और मध्य प्रदेश के लिए किन-किन योजनाओं को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (ङ) पंचवर्षीय योजनाएं देश की सामाजिक और आर्थिक विकास की व्यापक रूपरेखाएं तैयार करती हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है "सामाजिक न्याय और समानता सहित विकास"। राज्य सरकारें सम्पूर्ण राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्र के अन्तर्गत स्कीमें शुरु करने के लिए स्वतंत्र हैं। उड़ीसा, गुजरात और मध्य प्रदेश की योजनाओं में जिन क्षेत्रकों पर बल दिया गया है, वे सामाजिक सेवा, सिंचाई और विद्युत से संबंधित हैं। इन क्षेत्रकों के अन्तर्गत विस्तृत स्कीमों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अन्तिम रूप दिया जाना है। राज्य सरकारों द्वारा संसाधन जुटाव के पैरामीटर नौवीं योजना दस्तावेज में समाविष्ट हैं और उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा गुजरात राज्यों के लिए व्यापक क्षेत्रकीय आबंटन भी नौवीं योजना दस्तावेज में निर्दिष्ट हैं।

राज्यों पर, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य स्तरीय उद्यमों में सुधार लाकर और अपने गैर-योजना व्यय को कम करके अधिक संसाधन जुटाने के लिए भी जोर दिया गया है ताकि योजना के वित्त पोषण के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध हो जाएं।

Scheme for Unemployed Youth

2610. SHRIMATI BASANTI SARMA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have announced any new scheme for unemployed youth of the country to start their industrial business;

(b) if so, the details thereof;

(c) the number of applications received by